

दिनांक 30 जून 2015

नमस्कार मित्रों

नया सत्र की हार्दिक शुभ कॉमनाएँ । जिस तरह आकाश मे बरसात के लिए बादल उमड़ रहे हैं उसी तरह शिक्षा मंत्री जी के मन मे निजी विद्यालयों को किसी न किसी बहाने बंद कराने के विचार उमड़ रहे हैं ।

1. सरकार ने अपने शिक्षकों को नामॉकन का लक्ष्य दिया है अर्थात वे पहले तो मना करते थे लेकिन अब अपनी नोकरी बचाने के लिए बच्चे ढूढ़ते फिर रहे हैं ।
2. आरटीई मे लॉटरी बहुत पहले ही निकाल ली यह जानते हुए कि एडमीशन होगे नहीं एवं सीटे खाली रह जायेगी एवं जब एडमीशन होगे, तब आरटीई की लॉटरी बंद हो जायेगी और बच्चों को मजबूरन सरकारी स्कूल मे आना होगा । इससे भी नामॉकन बढ़ेगा उनका ।
3. बिना टीसी के प्रवेश पहले भी संभव नहीं था एवं अब भी नहीं है । सरकार ने अपने स्कूलों को बिना टीसी अस्थाई प्रवेश देने को कहा है, जो सामान्य प्रक्रिया है एवं हर बार होती आई है, लेकिन सरकार ने इस बार प्रचार – प्रसार करके यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिना टीसी ही प्रवेश हो जायेगा, आप तो आ जाओ ।
4. मान्यता के नियमों को कोई ढील देनी तो दूर, उनको और कठोर किया गया है ताकि नये स्कूल खुल ही नहीं सकें ।
5. पीपीपी मॉडल पर अपने रिश्तेदारों की बड़ी कम्पनियों को करोड़ों के सरकारी स्कूल मुफ्त मे दिये जा रहे हैं ।

दोस्तो मेरा यह सब बताने के पीछे सिर्फ दो ही मकसद है –एक – कि आप सर्तक एवं सजग रहे एवं लोगो को सरकारी भुलावे / झूँठ के बारे मे अवगत कराते रहे । ताकि आपका स्कूला प्रभावित ना हो । दूसरा – कि हम लगातार सरकार पर निगाह रखे हुए हैं एवं इन समस्याओ के समाधान के लिए संघर्षरत भी हैं । मौके की तलाश मे है क्योंकि अभी सरकारी अंधी है । मुख्यमंत्री/सुनती नहीं हैं और मंत्री तो चाहता ही नहीं है । सरकार को कोटा संभाग के दौरे पर बाहर निकलने दो । फिर इनको जवाब देते भारी पड़ेगा । अब मैं आपको उपरोक्त चारो तथ्यो से लड़ने की तरकीब बता रहा हूँ – ध्यान लगा कर करेगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा –

1. आप लोग भी अपने अभिभावकों एवं संभावित अभिभावकों से नियमित सम्पर्क बनाये रखें एवं सरकारी पढाई/परिणाम एवं निजी विद्यालयों के परिणाम के बारे में बता कर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर निजी विद्यालयों में ही पढ़ाने को प्रेरित करें। आप चाहे तो रामबाण वाक्य अपना सकते हैं – चाहे आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाये पर पढ़ाये निजी में ही क्योंकि यदि आपके बच्चे का जीवन संवर गया तो आपको जीवन संवर जायेगा। सरकारी स्कूल यदि अच्छे होते तो सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते क्या? उनके बच्चे तो निजी में और अपनी नोकरी बचाने के लिए आपके बच्चों को अपने पास

2. आरटीई अधिनियम में एडमीशन के लिए सत्र प्रारम्भ से 6 माह तक का प्रावधान है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। आप और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन अभिभावक चाहे तो उनके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करवा सकता है। मैंने इस बारे में पूरे नियमों के साथ एक पत्र अपनी वेबसाईट पर डाल दिया है। साथ ही मैंने पूरा एक भी साईट पर डाल दिया है वकील को दिखाने के लिए। आप लोग ऐसे पैरेन्ट्स को वह चिटठी लिख कर दे देवे एवं हो सके तो किसी वकील से बात करके आप ही उस पैरेन्ट्स के नाम से डायरेक्टर/डीईओ को नोटिस दिलवा देवे। फिर देखो कमाल झक मार कर एडमीशन ऑपन करना होगा। डरे नहीं। आप तो एक दो नोटिस दिलवावों एवं अभिभावकों से कहे कि चिन्ता नहीं करे ओपन करना होगा एवं एमपी एमएलए आदि के घर अभिभावकों के ले कर जा सकते हैं आप ...

3. बिना टीसी एडमीशन नहीं होता है। डायरेक्टर ने जो पत्र लिखा है उसमें भी स्पष्ट कहा है आप चाहे तो वह पत्र अपनी वेबसाईट से ले सकते हैं। उसमें कई बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं – 1. बिना टीसी के दिया गया एडमीशन अस्थाई होगा। दूसरा डीईओ टीसी दिलवाने की कोशिश करेगे अर्थात् टीसी तो जरूरी है तीसरा – सरकारी विद्यालय बच्चे की पात्रता की पूरी जाँच करे – अर्थात् किसी भी कक्षा में किसी भी छात्र की पात्रता की जाँच कर केवल और केवल एक मात्र साधन है अंकतालिका एवं टीसी जिसमें टीसी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको कानूनी बात और बताना चाहता हूँ कि आरटीई अधिनियम में बिना टीसी प्रवेश देने का प्रावधान है लेकिन वह इन नियमित छात्रों के लिए नहीं बल्कि 6 से 14 वर्ष के उन छात्रों के लिए है जिन्हौने किसी भी कक्षा में या स्कूल में नियमित अध्ययन नहीं किया हो। ऐसे छात्रों को भी किसी भी कक्षा में एडमीशन देने से पूर्व बहुत सारी ऑपचारिकताएँ करनी पड़ती हैं जो सरकारी तो कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही इस पत्र में डायरेक्टर ने लिखा है कि डीईओ जाँच करके ही मान्यता समाप्ति का प्रस्ताव भिजवायेंगे अर्थात् डीईओ आपसे

पूछेगा कि टीसी क्यों नहीं दी । जवाब मैं आज कल मेरी वेबसाईट पर डाल दूँगा । और पैसे बकाया होने पर टीसी नहीं देने पर कोई डीईओ आपकी मान्यता समाप्त नहीं कर सकता है । दूसरा निदेशक महोदय को नियमों का पता ही नहीं है कि मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया अब बदल गई है । केवल मान्यता नियमों में एक से अधिक शर्तों की पालना नहीं करने पर ही मान्यता ली जा सकती है । आपको याद दिला दूँ कि बोर्ड परीक्षाओं में अंक बढ़वाने वाले खाटूश्याम जी के देश बन्धु स्कूल की इतने बखड़े के बाद भी मान्यता निरस्त नहीं कर सके केवल निलम्बित ही कर सके हैं । सरकार यूँ ही डराती है । उसे मत

4. मान्यता नियमों में अगले साल एफ डी की छूट तो हो सकती है क्योंकि सीबीएसई मेरे कम है और ये सीबीएसई की नकल करते हैं ।
 5. पीपीपी मॉडल निश्चित रूप से हम सब के लिए खतरनाक है क्योंकि बड़ी कम्पनियों को खुली लूट की अनुमति होगी और उनका खर्चा नाम मात्र का होगा क्योंकि ना तो कम्पनियाँ केवल उन स्कूलों को लेगी जिनमें कमाई दिखाई देगी । एवं भूमि-भवन सरकार का होता ही है । यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कम्पनी अधिनियम में सीएसआर नाम एक फण्ड प्रत्येक कम्पनी को रखना होता है जिसके तहत कम्पनी को सामाजिक कार्य करने होते हैं अतः यह सरकार की बड़ी चाल है जिसमें वह करोड़ों का खर्च दिखायेगी एवं सीएसआर के तहत खर्च करने की बजाए पैदा करके ले जायेगी ।
-

दौस्तों मैं आपको सिर्फ इतना आगाह करना चाहता हूँ कि अब पहले वाली बात नहीं रही चुनौतियाँ बहुत हैं अतः आपको पहले से ज्यादा सर्तक रहना होगा । आप मेरे इन मैसेजेज को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं मनन करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ।
